



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
ART II—Section 3—Sub-Section. (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917

No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

का०आ० 280(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/95.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के कानूनी आदेश संख्या 157(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता में स्थित मैसर्स लिल्ली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिल्ली बार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक दोनों औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध का 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिग्रहण किया गया था और रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग, जो अब औद्योगिक पुर्ननिर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, में पश्चिम बंगाल सरकार के सचिव को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1995 तक की और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे। (देखिये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश) :

- सं० का०आ० 178(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 26 मार्च, 1982
 सं० का०आ० 688(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 25 सितम्बर, 1982
 सं० का०आ० 384(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 31 मई, 1983
 सं० का०आ० 936(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 29 दिसम्बर, 1983
 सं० का०आ० 469(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/84, तारीख 28 जून, 1984
 सं० का०आ० 967(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/84, तारीख 28 दिसम्बर, 1984
 सं० का०आ० 280(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/85, तारीख 30 मार्च, 1985
 सं० का०आ० 144(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/86, तारीख 31 मार्च, 1986
 सं० का०आ० 271(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/87, तारीख 30 मार्च, 1987
 सं० का०आ० 327(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/88, तारीख 30 मार्च, 1988
 सं० का०आ० 246(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/89, तारीख 31 मार्च, 1989
 सं० का०आ० 275(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/90, तारीख 30 मार्च, 1990
 सं० का०आ० 213(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/91, तारीख 26 मार्च, 1991
 सं० का०आ० 249(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/92, तारीख 30 मार्च, 1992
 सं० का०आ० 218(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/93, तारीख 31 मार्च, 1993 और
 सं० का०आ० 227(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/94, तारीख 31 मार्च, 1994

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 26 मार्च, 1996 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देती है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 26 मार्च, 1996 तक की, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 2(3)/80-सी०यु०एस०/आई०आर०एस०]

प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1995

S.O. 280(E)|18A|IDRA|95.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)|18A|IDRA|79 dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Barley Mills (Private) Limited, both located in Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as 'Authorised Controller'.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1995 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

- Nos. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82, dated the 26th March, 1982.
S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982.
S.O. 384(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,
S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,
S.O. 496(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,
S.O. 967(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th December, 1984,
S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985,
S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,
S.O. 271(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,
S.O. 327(E)|18A|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,
S.O. 246(E)|18A|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,
S.O. 275(E)|18A|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,
S.O. 213(E)|18A|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,
S.O. 249(E)|18A|IDRA|92, dated the 30th March, 1992,
S.O. 218(E)|18A|IDRA|93, dated the 31st March, 1993 and
S.O. 277(E)|18A|IDRA|94, dated the 31st March, 1994.

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 26th March, 1996.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of the Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 26th March, 1996.

[File No. 2(3)/80-CUS./IRS]
PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.